

Title: Need to announce special financial package for overall development of Bihar.

श्री सुकदेव पास्वान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य की वित्तीय हालत इतनी दयनीय है कि वहां से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य का शेर 25 प्रतिशत भी जुट नहीं पाता है। फलतः केन्द्र से योजना क्रियान्वयन के लिए आवंटित राशि बिना उपयोग के ही वापस हो जाती है। राज्य में 61.9 प्रतिशत पिछड़ापन है। देश के कुल गरीबों में से हर छः गरीबों में से एक बिहारी आंका गया है। 1980-81 के मूल्यों के आधार पर 1996-97 में प्रति व्यक्ति आय 1245 रुपए थी जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह 1997 रुपए और 2533 रुपए है। यहां विकास की गति भी अलग है। अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में जहां 4.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है वहीं बिहार राज्य में यह 0.7 प्रतिशत ही है। 1998-99 में व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि 27,750 करोड़ रुपए थी जबकि उनसे ऋण 7200 करोड़ रुपए ही था। ग्रामीण अंचलों में जमा राशि 3270 करोड़ रुपए थी जबकि ऋण 890 करोड़ रुपए ही था। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फिलहाल राज्य में अन्दरूनी स्रोतों से आय प्राप्त नहीं की जा सकती है।

अतः यदि बिहार राज्य को अंधेरे से प्रकाश में लाना है तो उसकी विशेष रूप से सहायता करनी पड़ेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बिहार राज्य के लिए विशेष सुविधाओं की तत्काल घोषणा करे।